



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 1995/वैशाख 8, 1911

No. 188]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 1995/VAISAKHA 8, 1917

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1995

(आयकर)

सा.का.नि. 369.(अ).— चूंकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और आर्थिक अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और वियतनाम समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच हुआ अनुबंधित करार, उक्त करार के अनुच्छेद-29 के अनुसार उक्त करार को लागू करने के लिए दोनों ही संबंधित राज्यों द्वारा अपने-अपने कानूनों के अन्तर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बारे में एक दूसरे के लिए अधिसूचना जारी करने के पश्चात् माह फरवरी, 1995 के दूसरे दिन से प्रवृत्त हो गया है :

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि उक्त करार के सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जाएंगे।

अनुबंध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य

और

वियतनाम समाजवादी गणराज्य

के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार और वियतनाम समाजवादी गणराज्य की सरकार,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए एक करार संपन्न करने की इच्छा से, नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद-1

वैयक्तिक क्षेत्र

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं।

अनुच्छेद-2

करार के अंतर्गत आने वाले कर

1. यह करार किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके राज-नैतिकके अंतरण उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से आय पर लगाए गए करों पर लागू होगा, भले ही ये किसी भी तरह से लगाए जाएं।

2. कुल आय अथवा आय के तत्वों पर चल अथवा अचल संपत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाषों पर लगाए गए करों और उद्यमियों द्वारा अदा की गयी मजदूरी अथवा वेतनों की कुल राशियों पर करों सहित लगाए गए सभी करों को आय पर करों के रूप में माना जाएगा।

3. जिन मौजूदा करों पर यह करार लागू होगा वे इस प्रकार हैं :

(क) भारत में :

आयकर जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधिभार शामिल है;

(जिन्हें इसके बाद “भारतीय कर” कहा जाएगा);

(ख) वियतनाम में :

(i) व्यक्तिगत आय कर;

(ii) लाभ कर; और

(iii) लाभ प्रेषण कर;

(जिन्हें इसके बाद “वियतनामी कर” कहा जाएगा)।

4. यह करार किसी भी समरूप अथवा सारतः इसी तरह के करों पर भी लागू होगा, जो करार पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएं। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक-दूसरे को सूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए हों।

अनुच्छेद-3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो :

(क) “भारत” पद से अभिप्रेत है—भारत का राज्य-क्षेत्र तथा उसमें शामिल राज्यक्षेत्रीय समुद्र तथा उसके ऊपर का वायुमंडलीय-क्षेत्र और कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र जिस पर भारतीय कानून तथा अन्तर-राष्ट्रीय कानून अथवा समुद्र के कानून पर यू. एन. अभिसमय के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता-संपन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हों;

(ख) “वियतनाम” पद से अभिप्रेत है—वियतनाम समाजवादी गणराज्य, जब यह भौगोलिक अर्थ में प्रयुक्त होगा जिसमें अभिप्रेत है इसके सभी राष्ट्रीय राज्य-क्षेत्र जिसमें इसके राज्य क्षेत्रीय समुद्र और इसके राज्य क्षेत्रीय समुद्र से परे और निकटवर्ती कोई क्षेत्र भी शामिल है, जिस पर वियतनाम का, समुद्र तथा इसकी भूमि और उर्ध्ववर्ती जल-साधनों के प्राकृतिक संसाधनों की खोज करने तथा इनका उपयोग करने के लिए वियतनामी कानून और अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रभुसत्ता संपन्न अधिकार हों;

(ग) “एक संविदाकारी राज्य” और “दूसरे संविदाकारी राज्य” पदों से, संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारत और वियतनाम अभिप्रेत है

(घ) “कंपनी” पद से कोई भी ऐसा निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है—जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अंतर्गत एक कंपनी अथवा निगमित निकाय के रूप में माना जाता है;

(ङ) “सक्षम प्राधिकारी” पद से अभिप्रेत है :

(i) भारत के मामले में, केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(ii) वियतनाम के मामले में, वित्त मंत्री अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि,

(च) “एक संविदाकारी राज्य का उद्यम” तथा “दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम” पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है;

(छ) “वित्तीय वर्ष” पद से अभिप्रेत है :

(i) भारत के मामले में, “पूर्ववर्ती वर्ष” जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित है;

(ii) वियतनाम के मामले में, कोई वारह-मास की अवधि वाला लेखा वर्ष;

(ज) “अन्तरराष्ट्रीय यातायात” पद से अभिप्रेत है—किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो निवाय उम स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो;

(झ) “राष्ट्रिक” पद से अभिप्रेत है—किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता धारण करने वाला कोई व्यक्ति और कोई कानूनी व्यक्ति, भागीदारी अथवा संस्था जिसे अपनी यह हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से उस रूप में प्राप्त होती हो;

(ञ) “व्यक्ति” पद में कोई व्यक्ति कोई कंपनी, व्यक्तियों का कोई निकाय और कोई ऐसी अन्य सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अंतर्गत एक कराधेय इकाई माना जाता है;

(ट) “कर” पद से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारतीय कर अथवा वियतनामी कर अभिप्रेत है, परन्तु इसमें ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में किसी भूल या चूक के संबंध में देय हो जिनके लिए यह करार लागू होता है अथवा जो उन करों के संबंध में लगाए गए अर्थव्यय को निरूपित करने है।

2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस करार के प्रवर्तन का संबंध है किसी शब्द का जो उसमें परिभाषित नहीं हुआ हो, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, तब तक वही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जिन पर यह करार लागू होता है।

अनुच्छेद-4

निवासी

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, “एक संविदाकारी राज्य का निवासी” पद से अभिप्रेत है—कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर उस राज्य में उसके कानूनों के अनुसार उसके अधिवास, निवास, प्रबंध का स्थान, पंजीकरण का स्थान अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण कर लगता हो।

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :

(क) उसे उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो यदि उसे दोनों संविदाकारी राज्यों में स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का एक निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं। (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र);

(ख) यदि उस संविदाकारी राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसको दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो;

(ग) यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है;

(घ) यदि वह दोनों ही राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे।

3. जहां व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका वास्तविक प्रबंधस्थान स्थित है।

अनुच्छेद-5

स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, “स्थायी संस्थापन” पद से कारोबार का वह एक निश्चित स्थान अभिप्रेत है जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार संपूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है।

2. “स्थायी संस्थापन” पद से में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) प्रबंध का कोई स्थान;

(ख) कोई शाखा;

(ग) कोई कार्यालय;

(घ) कोई कारखाना;

(ङ) कोई कार्यशाला;

(च) कोई खान, तेल अथवा गैस का कोई कुआं, कोई खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान;

(छ) कोई माल गोदाम जिसमें कोई व्यक्ति दूसरों के लिए भंडारण मुविधार्ण मुहैया कराता है; और

(ज) कोई भवन स्थल अथवा कोई निर्माण-कार्य अथवा संयोजन परियोजना अथवा उनसे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप, परन्तु जहां ऐसा स्थल परियोजना अथवा कार्यकलाप छः महीने से अधिक की अवधि के लिए चलता रहता है।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, “स्थायी संस्थापन” पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा :

(क) उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के केवल भंडारण, प्रदर्शन अथवा प्रासंगिक डिलीवरी के प्रयोजनार्थ मुविधार्णों का प्रयोग;

(ख) केवल भंडारण, प्रदर्शन अथवा प्रासंगिक डिलीवरी के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं का स्टॉक रखना;

(ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा संसाधित करने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं का स्टॉक रखना;

(घ) किसी उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं को केवल खरीदने अथवा सूचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना;

(ङ) किसी उद्यम के लिए केवल किसी अन्य दूसरे कार्यकलाप के प्रयोजनार्थ कारोबार का एक निश्चित स्थान रखना, जो प्रारंभिक अथवा सहायक स्वरूप का हो।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी स्वतंत्र हैमियत के किसी एजेंट से भिन्न कोई व्यक्ति जिस पर पैराग्राफ 5 लागू होता है, एक संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा हो तो किन्हीं कार्यकलापों के संबंध में जो वह व्यक्ति उद्यम के लिए करता है उस उद्यम का प्रथमोलिखित राज्य में स्थायी संस्थापन तभी माना जाएगा यदि ऐसा कोई व्यक्ति :

(क) जो उस राज्य में उस उद्यम की ओर से संविदा संपन्न करने का प्राधिकार रखता हो और वह आभ्यासिक रूप से उस प्राधिकार का प्रयोग करता हो जब तक कि ऐसे व्यक्ति के कार्यकलाप पैरा 3 में उल्लिखित कार्यकलापों तक सीमित न हों जिनकी वजह से, यदि उन्हें कारोबार के किसी निश्चित स्थान के जरिए किया गया हो, उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन कारोबार का यह निश्चित स्थान स्थायी संस्थापन नहीं बनेगा; अथवा

(ख) वह ऐसा कोई प्राधिकार नहीं रखता हो, लेकिन वह प्रथमोक्त राज्य में उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं का आभ्यासिक रूप से ऐसा स्टॉक रखता हो जिसमें से वह व्यक्ति उद्यम की ओर से नियमित रूप से माल अथवा पण्य-वस्तुओं की डिलीवरी करता हो।

5. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैमियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों। तथापि, तब ऐसे किसी एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः उस उद्यम की ओर से किए जाते हों तो उक्त स्थिति में इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अंतर्गत स्वतंत्र हैमियत का एजेंट नहीं समझा जाएगा।

6. यदि कोई कंपनी जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है किसी ऐसी कंपनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कंपनी द्वारा नियंत्रित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार

करती है तो मात्र इस तथ्य से ही उन दोनों में से कसी एक कंपनी को स्वतः ही दूसरी कंपनी का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा।

अनुच्छेद - 6

अचल सम्पत्ति से आय -

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय (इसमें कृषि और वानिकी से प्राप्त आय भी शामिल है) पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानून के अंतर्गत उसका अर्थ है जिसमें संबंधित सम्पत्ति स्थित है। इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे—अचल सम्पत्ति के अवमाधन के रूप में सम्पत्ति, पशुधन और उपस्कर जो कृषि और वानिकी में प्रयुक्त होते हों—ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए अथवा कार्य करने के लिए अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार। जलयान, नौकाएँ और वायुयान अचल सम्पत्ति के रूप में नहीं माने जाएंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराए पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाली आय पर लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद - 7

कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो। यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो स्थायी संस्थापन के कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष उत्पन्न हुआ माना जा सकता हो।

इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए "प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष" शब्द से अभिप्रेत है कि जहां कोई स्थायी संस्थापन उद्यम द्वारा की गई बातचीत, संविदाओं को निष्पन्न करने अथवा पूरा करने में सक्रिय रूप से भाग लेता है तब इसके होते हुए भी, कि उद्यम के दूसरे भागों ने भी उन सौदों में

हिस्सा लिया है, उन संविदाओं में उद्भूत उद्यम के लाभों का वह अनुपात स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुआ माना जाएगा क्योंकि उन सौदों के लिए स्थायी संस्थापन का अंशदान पूर्णतया उस उद्यम के द्वारा वहन किया जाता है।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम, दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण ये लाभ हुए माने जाएंगे, जिनके होने की तब अपेक्षा रहती, जब वह एक-समान या मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक-समान या मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता जिसका वह एक स्थायी संस्थापन है।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में, उन खर्चों की कटौती की अनुमति दी जाएगी जो स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ खर्च किए जाते हैं, जिनमें इस प्रकार खर्च किए गए कार्यकारी एवं सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, भले ही यह उस राज्य में किए गए हों जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित हो अथवा अन्यत्र किए गए हों तथा यह उस राज्य के उपबंधों के अनुसार तथा कराधान कानूनों की सीमाओं के अधीन किए गए हों।

4. इस अनुच्छेद की कोई भी बात किसी व्यक्ति के ऐसे मामलों की कर देयता के निर्धारण के संबंध में किसी संविदाकारी राज्य के किसी कानून के प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करती है जहां किसी स्थायी संस्थापन को प्राप्त होने वाले लाभों के निर्धारण के लिए उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी को सूचना उपलब्ध नहीं है बशर्ते कि कानून इस अनुच्छेद के सिद्धांतों के अनुकूल लागू किए जाएं।

5. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य में, उद्यम के कुल लाभों को उसके विभिन्न भागों के प्रति एक विभाजन के आधार पर, किसी स्थायी संस्थापन के कारण माने जाने वाले लाभों को निश्चित करने की प्रथा रही है, वहां पैराग्राफ 2 की कोई भी व्याख्या उस संविदाकारी राज्य को ऐसी प्रचलित विभाजन पद्धति से, कर योग्य लाभों को निश्चित करने से प्रतिबाधित नहीं करेगी, तथापि, विभाजन पद्धति ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में निहित सिद्धांतों के अनुसार होगा।

6. कोई लाभ केवल इस कारण किसी स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल या पण्यवस्तुएं खरीदी गयी हैं।

7. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्णनवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उनके विपरीत कोई ठोस तथा पथ्यित कारण नहीं हों।

8. जहां लाभों में आय की वे मंदा शामिल हैं जिनका विवेचन अलग से इस करार के अन्य अनुच्छेदों में किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों में प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद-8

जहाजरानी तथा वायु परिवहन

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर-राष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से प्राप्त लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयान के प्रचालन से प्राप्त लाभों में ये शामिल होंगे :

(क) जलयानों अथवा वायुयानों का पट्टे पर देने से होने वाली आय ;

(ख) आधानों (जिनमें ट्रेलर और आधानों के परिवहन के लिए संबंधित उपकरण भी शामिल हैं) के इस्तेमाल, रख-रखाव अथवा किराए पर देने से होने वाली आय ;

जहां पर ऐसा पट्टा अथवा ऐसा इस्तेमाल, रख-रखाव अथवा किराया, जैसा भी मामला हो, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जहाजों अथवा वायुयान के परिचालन के कारण हुआ हो।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पून, संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय परिचालन एजेंसी में भाग लेने से प्राप्त होने वाले लाभों पर भी लागू होंगे।

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयान के परिचालन से संबंधित निधियों पर ब्याज, जो कि सभी प्रकार के बैंक और जलयानों अथवा वायुयान और उनके कर्मियों के रख-रखाव के लिए अदायगियों के लिए रखा गया है, को ऐसे जलयानों अथवा वायुयान के परिचालन से प्राप्त आय अथवा लाभ समझा जाएगा और अनुच्छेद 11 के उपबंध ऐसे ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे।

अनुच्छेद-9

सहयोगी उद्यम

जहां :

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की प्रबंध व्यवस्था, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; अथवा

(ख) वे ही व्यक्ति, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की प्रबंध व्यवस्था, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं,

और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं, जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वहां ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद-10

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कंपनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी, उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसकी लाभांश अदा करने वाली कंपनी एक निवासी है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता, लाभांश का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर लाभांश की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

इस पैराग्राफ का उन लाभों के संबंध में कंपनी के कराधान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनमें से लाभांशों का भुगतान किया जाता है।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "लाभांश" शब्द का अभिप्राय, शेयरों अथवा अन्य अधिकारी से प्राप्त आम से है जो लाभ की भागीदारी के अणुदावे नहीं हैं और अन्य निर्गमित अधिकारों से प्राप्त आय से है, जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है, जो उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत शेयरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कंपनी निवासी है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है जिसकी लाभांश अदा करने वाली कंपनी निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है और जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामले में, यथा-स्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध लागू होंगे।

5. जहां कोई कंपनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वह यह दूसरा राज्य कंपनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर वहां तक किसी भी प्रकार का कर नहीं

लगाएगा जहां तक कि ऐसे लाभांश उस दूसरे राज्य के निवासी को अदा किए जाते हैं अथवा जहां तक कि जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों का अदायगी की जाती है, वह उस राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है और न ही उस दूसरे राज्य में कंपनी के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभ-संबंधी कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में ही हों।

अनुच्छेद-11

व्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले व्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. तथापि, इस प्रकार के व्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा, जिस राज्य में वह उद्भूत होता है परन्तु यदि प्राप्तकर्ता व्याज का हितभागी स्वामी है तो लगाया जाने वाला कर व्याज की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. पैरा 2 के उपबंधों के होते हुए भी :—

(क) एक संविदाकारी राज्य में व्याज पर उस राज्य में कर से छूट होगी बशर्ते कि वह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया जाता है और हितभागी रूप से अपने स्वामित्व में रखा जाता है :

(i) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण; अथवा

(ii) दूसरे संविदाकारी राज्य का केन्द्रीय बैंक;

(ख) एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले व्याज पर उस संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा अनुमोदित सीमा तक कर से छूट तब होगी जब यह व्याज (उप-पैराग्राफ (क) में उल्लिखित व्यक्ति से भिन्न) किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है और हितभागी रूप से अपने स्वामित्व में रखा जाता है जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है बशर्ते कि जिस लेन-देन के कारण अणु-दावा उद्भूत होता है उसे प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किया गया है।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "व्याज" शब्द से अभिप्रेत है—प्रत्येक प्रकार के अणु-संबंधी दावों से प्राप्त आय, चाहे वे कंपक द्वारा प्रतिभूत हो अथवा नहीं हो और चाहे उन्हें अणु-दाता के लाभों में भागीदारी का कोई अधिकार

प्राप्त हो अथवा नहीं हो और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंध-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों से प्राप्त आय, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंध-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हों। देर से की गई अदायगी के लिए, अर्थदंड संबंधी प्रभावों को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, व्याज नहीं समझा जाएगा।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि व्याज का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें व्याज उत्पन्न हुआ हो, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता हो, और जिस ऋण-दावे के बारे में व्याज अदा किया गया हो, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध हो। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

6. व्याज किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ तभी माना जाएगा, जब व्याज अदा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य, उस राज्य का कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई निवासी हो। किन्तु जहां व्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा एक निश्चित स्थान है, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था, जिस पर व्याज की अदायगी की जाती है और इस प्रकार का व्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तो इस प्रकार का व्याज उस राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां व्याज अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण की गई व्याज की रकम, उस ऋणदावे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए व्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है जिसके लिए इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में अदायगी के अतिरिक्त भाग पर, इस करार के अन्य उपबन्तों का सम्यक् अनुपालन करते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद-12

रायल्टियां

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियों पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों, उस राज्य के कानूनों के अनुसार लगाया जा सकेगा, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता रायल्टियों का हितभागी स्वामी हो तो इस प्रकार प्रभारित कर, रायल्टियों की सकल राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टियां" शब्द से तात्पर्य किसी भी प्रकार की ऐसी अदायगियों से है जो साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियां, जिसमें चलचित्र, फिल्में या रेडियो अथवा दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली फिल्में या टेपें शामिल हैं, कोई पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया के किसी भी कापीराइट के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्कर अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त हों।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियां उद्भूत होती हैं, उसमें स्थित स्थायी संस्थान के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं निष्पादित करता है तथा वह अधिकार अथवा संपत्ति जिनके संबंध में रायल्टियां अदा की जाती हैं, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15, जैसा भी मामला हो, लागू होगा।

5. किसी संविदाकारी राज्य में रायल्टियां उद्भूत हुई मानी जाएंगी यदि अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। परन्तु जहां रायल्टियों के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा नहीं है, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान हो जिनके संबंध में रायल्टियां अदा करने की देनदारी उत्पन्न हुई हो तथा ऐसी रायल्टियां ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हैं तब ऐसी रायल्टियों के लिए फीस उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

6. जहां अदा करने वाले तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और कुछ अन्य व्यक्तियों के बीच विशिष्ट संबंध होने के कारण रायल्टियों की राशि, वे अधिकार अथवा सूचना जिसके संबंध में वे अदा की जाती हैं, को ध्यान में रखते हुए उस राशि से बढ़ जाती है जो ऐसे संबंधों के नहीं होने की स्थिति में अदा की गयी होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगियों का अतिरिक्त भाग इस करार के दूसरे वर्णित उपबंधों का उचित ध्यान रखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाए जाने योग्य रहेगा।

अनुच्छेद-13

तकनीकी सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गयी तकनीकी फीस पर दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. तथापि, ऐसी तकनीकी फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वह उद्भूत हुई हो, उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा लेकिन यदि प्राप्तकर्ता तकनीकी फीस का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर, तकनीकी फीस की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "तकनीकी फीस" शब्द में तकनीकी, प्रबंधकीय अथवा परामर्शदात्री स्वरूप की सेवाओं के प्रतिफल के रूप में अदायगियां करने वाले व्यक्ति के कर्मचारी को की गयी अदायगियों से भिन्न किसी व्यक्ति को की गयी किसी भी रकम की अदायगियां अभिप्रेत हैं।

4. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि तकनीकी फीस का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें तकनीकी फीस उद्भूत होती है उसमें स्थित स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं निष्पादित करता है और तकनीकी फीस ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा ऐसी सेवाओं के प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध, जैसा भी मामला हां लागू होंगे।

5. एक संविदाकारी राज्य में तकनीकी फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएगी, जब तकनीकी फीस अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण या उसका कोई सांविधिक निकाय अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। तथापि, जहां तकनीकी फीस अदा करने वाले व्यक्ति का चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, एक संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन हो इनके संबंध में तकनीकी फीस अदा करने का वचन दिया गया हो और ऐसी तकनीकी फीस उस स्थायी संस्थापन द्वारा बहन की जाती हो, तब ऐसे तकनीकी फीस उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन स्थित है।

6. जहां अदाकर्ता और प्राप्तकर्ता अथवा उन दोनों के बीच और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी प्रकार का विशेष संबंध होने के कारण, किसी भी कारण से प्रदत्त तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की मात्रा उस राशि से बढ़ जाती है जिसके लिए ऐसा संबंध न होने के कारण अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गयी होती, तब इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित राशि पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगी के अतिरिक्त भाग पर इस करार के अन्य उपबंधों का सम्यक अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 14

पूंजीगत अभिलाभ

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति के अन्तरण से एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. ऐसी चल संपत्ति के अन्तरण से होने वाले अभिलाभों पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के पास दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की व्यावसायिक संपत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल-संपत्ति के अन्तरण से होने वाले अभिलाभों पर, जो संपत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वयंसेवक वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसी स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अन्तरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं। उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

3. अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से संबंधित चल-संपत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका कि अन्तरणकर्ता निवासी है।

4. किसी ऐसी कंपनी के पूंजीगत स्टॉक के शेयरों के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर, जिसकी संपत्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सिद्धान्ततः किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल-संपत्ति हो, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

5. पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न, किसी ऐसी कंपनी के शेयरों के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर, जो संविदाकारी राज्य की एक निवासी कंपनी हो, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

6. पैरा 1, 2, 3, 4 और 5 में उल्लिखित संपत्ति से भिन्न किसी संपत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभ उस राज्य में कर योग्य होंगे जिसका अन्तरणकर्ता निवासी हो।

अनुच्छेद 15

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वरूप वाले उसी प्रकार के अन्य कार्यकलापों से प्राप्त आय, निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर जिनमें जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल उस राज्य में कराधेय होगी :

(क) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है, तो उस मामले में, उस दूसरे राज्य में केवल उतनी आय पर कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है अथवा

(ख) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की अवधि अथवा अवधियां संगत "वित्तीय वर्ष" में कुल मिलाकर 183 दिनों अथवा उसमें अधिक हो, तो उस मामले में आय के केवल उतने ही भाग पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा जो दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्य-कलापों में प्राप्त होती हो।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्य-कलाप तथा चिकित्सकों, कल्प-चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दंत-चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप भी शामिल हैं।

अनुच्छेद-16

परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 17, 18, 19, 20, 21 तथा 22 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों मजदूरियों और इस प्रकार के अन्य परिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा जब तक कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया हो। यदि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में किया गया है तो जो पारिश्रमिक वहां में प्राप्त होता है, उस पर, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त परिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

(क) प्राप्तकर्ता संगत "वित्तीय वर्ष" अथवा कराधान अवधि के दौरान, जैसा भी मामला हो, ऐसी अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य में रहा है जो कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक नहीं है ;

(ख) पारिश्रमिक ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से है अदा किया गया है जो दूसरे राज्य का निवासी है ; और

(ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा किसी निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है जो नियोजक के दूसरे राज्य में हो।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, अन्तर्राष्ट्रीय सन्धिमान में एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित जनयान अथवा वायुयान पर किये गये नियोजन के संबंधों में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

992 GI 95—2

अनुच्छेद-17

निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस तथा इसी तरह की अन्य अदायगियां जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कंपनी, जो अन्य संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मण्डल के सदस्य की हैमियत से प्राप्त की गयी हो, उन पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

अनुच्छेद 18

मनोरंजनकर्तियों और एथलीटों द्वारा अर्जित आय

1. अनुच्छेद 15 तथा 16 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार अथवा संगीतकार अथवा किसी एथलीट के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के अपने वैयक्तिक कार्यकलापों में प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी एथलीट द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए वैयक्तिक कार्य-कलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता अथवा एथलीट को प्राप्त नहीं हो, अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुच्छेद 7, 15 तथा 16 के उपबंधों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा एथलीट के कार्यकलाप किए जाते हैं।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी एथलीट द्वारा, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में उसी हैसियत में किए गए अपने वैयक्तिक कार्यकलापों से अर्जित आय प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में ही कर-योग्य होगी, यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में कार्यकाल प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की जिसमें उसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल हैं, सार्वजनिक निधियों में पूर्णतः अथवा पर्याप्त रूप से समर्थित होते हों।

4. पैराग्राफ 2 तथा अनुच्छेद 7, 15 तथा 16 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी एथलीट द्वारा उसी हैमियत में एक संविदाकारी राज्य में किए गए वैयक्तिक कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय, मनोरंजनकर्ता अथवा स्वयं एथलीट को प्राप्त नहीं होती है परन्तु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है, तो उस मामले में वह आय केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कर-योग्य होगी, यदि वह अन्य व्यक्ति, उस दूसरे राज्य, जिसमें उसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल हैं, की सार्वजनिक निधियों में पूर्णतः अथवा पर्याप्त समर्थित होता हो।

अनुच्छेद - 19

सरकारी सेवा के संबंध में पारिश्रमिक तथा पेंशन

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उसके उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए की गयी सेवाओं के संबंध में अदा किए गए, पेंशन से भिन्न पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में ही कर लग सकेगा ;
- (ख) तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लग सकेगा, यदि सेवाएं उस दूसरे राज्य में की जाती हैं और व्यक्ति उस राज्य का निवासी है, जो :
 - (i) उस राज्य का एक राष्ट्रिक है; अथवा
 - (ii) मात्र सेवाएं पेश करने के प्रयोजन से उस राज्य का निवासी नहीं बना हो ।
2. (क) किसी संविदाकारी अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अथवा उसके द्वारा सृजित कोष उसमें से किसी व्यक्ति को उसके द्वारा उस राज्य अथवा उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए की गयी सेवाओं के संबंध में अदा की गयी पेंशन पर केवल उसी राज्य में कर लग सकेगा ;
- (ख) लेकिन, ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल तभी कर लग सकेगा यदि व्यक्ति उस अन्य राज्य का एक निवासी तथा राष्ट्रिक हो ।

3. अनुच्छेद 16, 17 तथा 20 के उपबंध, किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए गए किसी कारोबार के सिलसिले में प्रदान की गयी सेवाओं के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 20

गैर-सरकारी पेंशन तथा वार्षिकियां

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के स्रोतों से प्राप्त अनुच्छेद 19 में उल्लिखित किसी पेंशन से भिन्न किसी पेंशन अथवा किसी वार्षिकी पर कर केवल प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में लगेगा ।
2. "पेंशन" पद से पिछली सेवाओं के लिए प्रतिफल के रूप में अथवा सेवाओं के निष्पादन के दौरान हुई क्षतियों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में की जाने वाली आवधिक अदायगी अभिप्रेत है ।
3. "वार्षिकी" पद से जीवन-काल में अथवा जैसी विनिर्दिष्ट या अनिश्चित समयावधि के दौरान धन-राशि अथवा उसके बराबर मूल्य में पर्याप्त तथा पूर्ण प्रतिफल की

अदायगी करने के दायित्व के अंतर्गत आवधिक रूप में निश्चित समय पर अदायगी-योग्य एक निश्चित राशि अभिप्रेत है ।

अनुच्छेद - 21

विद्यार्थियों और प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त की गयी अदायगियां

1. किसी विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य में उपस्थित है, निम्न-लिखित पर दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी :

- (क) उस दूसरे राज्य में वाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा उसके भरण-पोषण, शिक्षण अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ की गयी अदायगियां; और
- (ख) उस दूसरे राज्य में नियोजन से प्राप्त पारिश्रमिक की राशि किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित मुद्राओं में जैसा भी मामला हो, 2000 अमरीकी डालर अथवा उससे अधिक न हो, बशर्ते कि ऐसा नियोजन उसके अध्ययन से सीधे संबंधित हो अथवा यह उसके रख-रखाव के लिए किया जाए ।

2. इस अनुच्छेद के लाभ केवल ऐसी अवधि के लिए लागू होंगे जो कि शुरू किए गए शिक्षण अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया अपेक्षित हों, परन्तु किसी भी हालत में किसी व्यक्ति को इस अनुच्छेद के लाभ उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके प्रथमतः पहुंचने की तारीख से लगातार पांच वर्षों से अधिक के लिए प्राप्त नहीं होंगे ।

अनुच्छेद - 22

प्रोफेसरो, अध्यापकों और शोध अध्यापकों के द्वारा प्राप्त की गयी अदायगियां

1. किसी प्रोफेसर अथवा अध्यापक की, जो दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा किसी अन्य अनुमोदित संस्थान में शिक्षण अथवा शोधकार्य अथवा दोनों कार्यों के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तत्काल पूर्व दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य का निवासी है अथवा था, उसके उक्त दूसरे राज्य में पहुंचने की तारीख से दो वर्षों से अधिक की अवधि के लिए ऐसे अध्यापन अथवा शोधकार्य के लिए प्राप्त किसी पारिश्रमिक पर उक्त दूसरे संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी ।

2. यह अनुच्छेद ऐसे शोधकार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा शोधकार्य मूलतः किसी व्यक्ति-विशेष अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया गया हो ।

3. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनों के लिए, "अनुमोदित संस्थान" का अर्थ किसी ऐसे संस्थान से है जिसे इस संबंध में संबंधित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

अनुच्छेद - 23

अन्य आय

1. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें जहां-कहीं वे उद्भूत होती हों और जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उग राज्य में कराधेय होंगी।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारबार करता है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है, तथा ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति, जिसके संबंध में ऐसी आय ग्राह्य की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदों पर भी, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है तथा जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होती हैं, उस दूसरे राज्य में भी कर लगेगा।

अनुच्छेद - 24

दोहरे कराधान का परिहार करना

1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य में प्रवृत्त कानून, संबंधित संविदाकारी राज्य के आय के कराधान के मामलों में लागू रहेंगे सिवाए ऐसे मामलों के जहां पर इस करार में उनके विपरीत कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया जाता है।

2. जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है, जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा, वहां प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य, चाहे प्रत्यक्ष रूप से अथवा कटौती के द्वारा उस निवासी की आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में अदा की गई आयकर की रकम के बराबर की रकम पर कर की कटौती की अनुमति देगा। तथापि, ऐसी कटौती की रकम, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में आयकर (कटौती दिए

जाने से पूर्व यथा-संगणित) के उस भाग से अधिक नहीं होगी जो कि ऐसी आय के कारण हो जिस पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित दूसरे संविदाकारी राज्य में अदा किए गए कर में भी शामिल माना जाएगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत स्वीकृत किए गए कर प्रोत्साहनों के न दिए जाने पर देय होता और जो आर्थिक विकास को उन्नत करने के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं।

अनुच्छेद - 25

सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रियों पर, दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं होगी जो उस कराधान से और उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रियों पर एक-समान परिस्थितियों में लागू होती हो अथवा लागू की जानी हो।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन पर लगाया जाने वाला कर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उस कर से अपेक्षाकृत कम अनुकूल नहीं होगा जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में समान कार्यकलापों के लिए एक-समान परिस्थितियों में लगे हुए उद्यमों पर लगाया जाता है। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के लाभों पर कर की ऐसी दर लगाने से रोकना है जो कि उस दर से अधिक है जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के उसी प्रकार के लाभों पर लगाई जाती है और न ही इस प्रकार के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के प्रतिकूल है।

3. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि वह उन व्यक्तियों को जो कि उस राज्य के निवासी नहीं हैं, कर प्रयोजनों के लिए किसी प्रकार की ऐसी व्यक्तिगत छूटें, राहतें, घटौतियां अथवा कटौतियां मंजूर करें जो कि कानून के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को उपलब्ध हैं जो वहां के निवासी हैं।

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व में अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में वैसी ही परिस्थितियों के अधीन ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी कोई भी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से तत्संबंधी किन्हीं भी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हो, जो प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य समरूप उद्यमों पर लगाई जाती है अथवा लगाई जा सकती है।

5. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 और 4 के उपबंध वियतनाम के लाभ प्रेषण कर पर लागू नहीं होंगे, जो किसी भी स्थिति में प्रेषित लाभों की सकल रकम के 10 प्रतिशत और कृषि उत्पादन संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में वियतनामी कराधान से अधिक नहीं होंगे।

6. इस अनुच्छेद में "कराधान" पद का अर्थ है वे कर जो इस करार के विषय हैं।

अनुच्छेद - 26

पारस्परिक करार कार्य-विधि

1. जहां किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्य-वाहियों के कारण इस प्रकार का कर लगाया जाएगा जो कि इस करार के उपबंधों के अनुकूल नहीं है तो वह उन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों में उपचारों की व्यवस्था होने के बावजूद भी, उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह निवासी है। यह मामला उस कार्रवाई का नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीन वर्षों के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके कारण कर लगाया गया था जो इस करार के उपबंधों के अनुकूल नहीं है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के निवारण की दृष्टि से, जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। किए गए किसी भी समझौते को कार्यान्वित किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों में कोई भी समय-सीमा निर्धारित हो।

3. इस करार की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाई अथवा गंकाएं उत्पन्न होने पर संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी से उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। दोहरे कराधान को दूर करने के लिए, उन मामलों जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं की गयी है, उनके संबंध में भी एक-दूसरे से परामर्श कर सकते हैं।

4. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पूर्ववर्ती पैराग्राफों को ध्यान में रखकर समझौते पर पहुंचने के लिए एक-दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं, यदि किसी समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से विचारों का मौखिक आदान-प्रदान उपयुक्त हो, तो ऐसा आदान-प्रदान एक आयोग के माध्यम से किया जा सकता है जिसमें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल हों।

अनुच्छेद - 27

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का (दस्तावेजों सहित) आदान-प्रदान करेंगे, जो करार के उपबंधों अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित आन्तरिक कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है जो इस करार के अंतर्गत आते हैं जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था करार के प्रतिकूल नहीं हो ताकि विशेष रूप से ऐसे करों की धोखाधड़ी अथवा अपव्ययन को रोका जा सके। किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गयी कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार कि उस राज्य के आन्तरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गयी सूचना मानी जाती है। तथापि, यदि सूचना भेजने वाले राज्य में सूचना को मूलतः गुप्त समझा जाता है तो उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा, जो उन करों का निर्धारण करने अथवा उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपराधों का निर्धारण करने से संबंध हों। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए करेंगे परन्तु वे सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाही अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। सक्षम प्राधिकारी विचार विमर्श के माध्यम से उन मामलों से संबंधित समुचित शर्तों, पद्धतियों और तकनीकों को विकसित करेंगे जिनके बारे में सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा, जिनमें जहां कहीं उपयुक्त हो, कर अपव्ययन के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान भी शामिल है।

2. सूचना अथवा दस्तावेजों का आदान-प्रदान या तो किसी नेमी आधार पर स्वतः किया जा सकता है अथवा विशेष मामले के संदर्भ में अनुरोध करने पर अथवा दोनों के लिए किया जाएगा। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी समय समय पर ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सूची पर सहमत होंगे जिन्हें नेमी आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा।

3. किसी भी स्थिति में, पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा:—

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;

(ख) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है ;

- (ग) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सप्लाई करना जिसमें कोई ध्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा रोजगार संबंधी भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो अथवा ऐसी सूचना जिसको प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकूल है।

अनुच्छेद - 28

राजनयिक और कौमुली अधिकारी

इस करार की किसी भी बात से राजनयिक अथवा कौमुली अधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत प्राप्त विस्तीय विवेकाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद 29

प्रवर्तन

दोनों संविदाकारी राज्यों में से प्रत्येक राज्य, इस करार की लागू करने के लिए अपनी विधि के अंतर्गत अपेक्षित कार्य-विधियों के पूरा किए जाने के बारे में दूसरे राज्य को अधिसूचित करेगा। यह करार इन अधिसूचनाओं में से बाद में जारी की गयी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा और इसका निम्नलिखित प्रभाव होगा :

- (क) भारत में, उस कैलेण्डर वर्ष के जिसमें अधिसूचनाओं का पत्र दिया जाना है, के अगले अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी पूर्ववर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में ;

(ख) वियतनाम में :

- (i) खात पर रोके गए करों के संबंध में जिस कैलेण्डर वर्ष में यह करार प्रभावी होगा उसके अनुवर्ती वर्ष के जनवरी माह की पहली तारीख को अथवा उसके पश्चात् आदा की गयी कर-योग्य राशि के संबंध में ;
- (ii) अन्य वियतनामी करों के संबंध में जिस कैलेण्डर वर्ष में यह करार प्रभावी होगा उसके अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष तथा बाद के वर्षों में उद्भूत होने वाली आय, लाभ अथवा अभिलाभों के संबंध में।

अनुच्छेद - 30

समापन

यह करार अनिश्चित समय तक लागू रहेगा, परन्तु दोनों में से कोई भी एक संविदाकारी राज्य इस करार के लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के पूरा हो जाने के बाद आरम्भ होने वाले किसी कैलेण्डर वर्ष के जून मास की तीस तारीख को अथवा इससे पहले राजनयिक माध्यम से दूसरे संविदाकारी राज्य को करार के समापन की लिखित तौर पर सूचना दे सकता है और ऐसी परिस्थिति में यह करार निम्नलिखित के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा -

- (क) भारत में, जिस कैलेण्डर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया जाता है उस कैलेण्डर वर्ष के अगले अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल मास की पहली तारीख को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी पूर्ववर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में ;

(ख) वियतनाम में :

- (i) खात पर रोके गए करों के संबंध में जिस कैलेण्डर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया जाता है, उसके अनुवर्ती वर्ष के जनवरी माह की पहली तारीख को अथवा उसके पश्चात् आदा की गयी कर-योग्य राशि के संबंध में ;
- (ii) अन्य वियतनामी करों के संबंध में, जिस कैलेण्डर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया जाता है, उसके अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष तथा बाद के वर्षों में उद्भूत होने वाली आय, लाभ अथवा अभिलाभों के संबंध में।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए उनकी संबंधित सरकारों द्वारा विधिवत् रूप में प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

हस्ताक्षरों में वर्ष एक हजार नौ सौ चौरानवे के सितम्बर मास के सातवें दिन हिन्दी, वियतनामी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो पाठों में निष्पन्न किया गया। अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ को प्रामाणिक माना जाएगा।

भारत गणराज्य वियतनाम समाजवादी गणराज्य की सरकार की ओर से की सरकार की ओर से

(भुवनेश चतुर्वेदी)

(हो ते)

राज्य मंत्री

मंत्री

प्रधान मंत्री कार्यालय

वित्त मंत्रालय

[अधिसूचना सं. 9758(फा. सं. 503/7/91 एफ. टी. डी.)]

वी. बी. श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 28th April, 1995

NOTIFICATION

INCOME-TAX

G.S.R. 369(E).—Whereas the annexed Agreement between the Government of Republic of India and the Government of the Socialist Republic of Vietnam for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has come into force on the 2nd day of February, 1995 after the notification by both the Contracting States to each other of the completion of the procedures required under their laws for bringing into force of the said Agreement in accordance with Article 29 of the said Agreement ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

Agreement between The Republic of India and The Socialist Republic of Vietnam for the avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income

The Government of Republic of India

and

The Government of the Socialist Republic of Vietnam

Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Have agreed as follows :

ARTICLE

Personal Scope

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

ARTICLE 2

Taxes Covered

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises.

3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are :

(a) in India :

the income tax including any surcharge thereon ;

(hereinafter referred as "Indian tax") ;

(b) in Vietnam .

(i) the personal income tax ;

(ii) the profit tax ; and

(iii) the profit remittance tax ;
(hereinafter referred to as "Vietnamese tax").

4. The Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

ARTICLE 3

General Definitions

1. In this Agreement, unless the context otherwise requires :

(a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdictions, according to the Indian law and in accordance with international law or the U.N. Convention on the Law the Sea ;

(b) the term "Vietnam" means the Socialist Republic of Vietnam ; when used in a geographical sense, it means all its national territory, including its territorial sea and any area beyond and adjacent to its territorial sea, within which Vietnam, by Vietnamese legislation and in accordance with international law, has sovereign rights of exploration for and exploitation of natural resources of the sea bed and its sub-soil and superjacent watermass ;

(c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" means India or Vietnam as the context requires ;

(d) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate under the taxation law in force in the respective Contracting States ;

(e) the term "competent authority" means :

(i) in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue or their authorized representative ; and

- (ii) in the case of Vietnam, the Minister of Finance or his authorized representative ;
- (f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" means respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State ;
- (g) the term "fiscal year" means :
 - (i) in the case of India, "previous year" as defined under Section 3 of the Income-tax Act, 1961 ; and
 - (ii) in the case of Vietnam, the accounting year comprising of a twelve-month period ;
- (h) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State ;
- (i) the term "national" means any individual, possessing the nationality of a Contracting State and any legal person, partnership or association deriving its status from the laws in force in the Contracting State ;
- (j) the term "person" includes an individual, a company, a body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States ;
- (k) the term "tax" means India tax or Vietnamese tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes.

2. As regards the application of the Agreement by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Agreement applies.

ARTICLE 4

Resident

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of registration or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows :

- (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him: if he has a permanent

home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests) ;

- (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has no permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode ;
- (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national ;
- (d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

ARTICLE 5

Permanent Establishment

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially :

- (a) a place of management ;
- (b) a branch ;
- (c) an office ;
- (d) a factory ;
- (e) a workshop ;
- (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources ;
- (g) a warehouse, in relation to a person providing storage facilities for others ; and
- (h) a building site or construction or assembly project or supervisory activities in connection therewith ; but only where such site, project or activity continues for a period of more than six months.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or occasional delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise ;

- (b) the maintenance of a stock of goods of merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or occasional delivery ;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise ;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information for the enterprise ;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person—other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies—is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person :

- (a) has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 3 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph ; or
- (b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

ARTICLE 6

Income from Immovable Property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

ARTICLE 7

Business Profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may also be taxed in the other State but only so much of them as is attributable directly or indirectly to that permanent establishment.

The words "directly or indirectly" mean, for the purposes of this Article, that where a permanent establishment takes an active part in negotiating, concluding or fulfilling contracts entered into by the enterprise, then notwithstanding that other parts of the enterprise have also participated in those transactions, there shall be attributed to the permanent establishment that proportion of profits of the enterprise arising out of those contracts as the contribution of the permanent establishment to those transactions bears to that of the enterprise as a whole.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the tax laws of that State.

4. Nothing in this Article shall affect the application of any law of a Contracting State relating to the determination of the tax liability of a person in cases where information is not available to the competent authority of that State in order to determine the profits to be attributed to a permanent establishment, provided that law shall be applied consistently with the principles of this Article.

5. In so far as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary. The method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

6. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

7. For the purposes of the preceding paragraphs the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

8. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

ARTICLE 8

Shipping and Air Transport

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. For the purposes of this Article, profits from the operation of ships or aircraft in international traffic include :

- (a) income from the lease of ships or aircraft; and
- (b) profits from the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers);

Where such lease or such use, maintenance or rental, as the case may be, is incidental to the operation of ships or aircraft in international traffic.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

4. For the purposes of this Article, interest on funds connected with the operation of ships or aircraft in international traffic earmarked for the purpose of payments of all kinds of wages and maintenance of ships or aircraft and their crew shall be regarded as income or profits derived from the operation of such ships or aircraft and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.

ARTICLE 9

Associated Enterprises

Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by the reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

ARTICLE 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in res-

pect of which the dividends, are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other Contracting State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

ARTICLE 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of such interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2,

(a) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by :

(i) the Government, a political sub-division or a local authority of the other Contracting State, or

(ii) the Central Bank of the other Contracting State;

(b) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that Contracting State to the extent approved by the Government of that State if it is derived and beneficially owned by any person [other than a person referred to in sub-paragraph (a)] who is a resident of the other Contracting State provided that the transaction giving rise to the debt-claim has been approved in this regard by the Government of the first-mentioned Contracting State.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

ARTICLE 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, or films; or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business

in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

ARTICLE 13

Technical Fees

1. Technical fees arising in a Contracting State which are derived by a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such technical fees may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the technical fees, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the technical fees.

3. The term "technical fees" as used in this Article means payments of any kind to any person, other than to an employee of the person making the payments, in consideration for any services of a technical, managerial or consultancy nature.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the technical fees, being a resident of a Contracting State carries on business in the other Contracting State in which the technical fees arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services, and the technical fees are effectively connected with such permanent establishment or such services. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

5. Technical fees shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a statutory body thereof, or a resident of that State. Where, however, the person paying the technical fees, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the obligation to pay the technical fees was incurred, and such technical fees are borne by that permanent establishment, then such technical fees shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the technical fees paid, exceeds for whatever reason, the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State due regard being had to the other provisions of this Agreement.

ARTICLE 14

Capital Gains

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property, referred to in Article 6, and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

4. Gains from the alienation of share of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.

5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.

6. Gains from the alienation of any property other than that mentioned in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

ARTICLE 15

Independent Personal Services

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State.

- (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or
- (b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in the relevant fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

ARTICLE 16

Dependent Personal Services

1. Subject to the provisions of Articles 17, 18, 19, 20, 21 and 22, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if :

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant fiscal year; and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State.

ARTICLE 17

Directors' Fees

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

ARTICLE 18

Income Earned by Entertainers and Athletes

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer such as theater, motion picture, radio or television artists, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. While income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 15 and 16, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 income derived by an entertainer or an athlete who is a resident of a Contracting State from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State, if the activities in the other Contracting State are supported wholly or substantially from the public funds of the first-mentioned Contracting State, including any of its political subdivisions or local authorities.

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 and Articles 7, 15 and 16, where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such in a Contracting State accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income shall be taxable only in the other Contracting State, if that other person is supported wholly or substantially from the public funds of the other State, including any of its political subdivisions or local authorities.

ARTICLE 19

Remuneration and Pensions in respect of Government Service

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who :

- (i) is a national of that State; or

- (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of that other State.

3. The provisions of Articles 16, 17 and 20 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

ARTICLE 20

Non-government Pensions and Annuities

1. Any pension, other than a pension referred to in Article 19, or any annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State shall be taxed only in the first-mentioned Contracting State.

2. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of past services or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.

3. The term "annuity" means a stated sum payable, periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money's worth.

ARTICLE 21

Payments Received by Students and Apprentices

1. A student or business apprentice who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State and who is present in that other State solely for the purpose of his education or training, shall be exempt from tax in that other State on :

- (a) payments made to him by persons residing outside that other State for the purposes of his maintenance, education or training; and
- (b) remuneration from employment in that other State, in an amount not exceeding US \$2000 or its equivalent in respective currencies during any fiscal year, as the case may be, provided that such employment is directly related to his studies or is undertaken for the purpose of his maintenance.

2. The benefits of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article for more than five consecutive years from the date of his first arrival in that other Contracting State.

ARTICLE 22

Payments received by Professors, Teachers and Research Scholars

1. A professor or teacher who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college, school or other approved institution in that other Contracting State shall be exempt from tax in that other State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other State.

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

3. For the purposes of paragraph 1, "approved institution" means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned Contracting State.

ARTICLE 23

Other Income

1. Subject to the provisions of paragraph 2, items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, which are not expressly dealt with in the foregoing Articles of this Agreement, shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to the income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement and arising in other Contracting State may also be taxed in that other State.

ARTICLE 24

Avoidance of Double Taxation

1. The laws in force in either of the Contracting States will continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Agreement.

2. Where a resident of a Contracting State derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in the other Contracting State, the first-mentioned Contracting State shall allow as a deduction from the tax on the income of

that resident an amount equal to the income tax paid in the other Contracting State whether directly or by deduction. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax (as computed before the deduction is given) in the first-mentioned Contracting State which is attributable to the income which may be taxed in the other Contracting State.

3. The tax paid in the other Contracting State mentioned in paragraph 2 of this Article shall be deemed to include the tax which would have been payable but for the tax incentives granted under the laws of that Contracting State and which are designed to promote economic development.

ARTICLE 25

Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances. This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which an enterprise of the other Contracting State has in the first-mentioned State at a rate higher than that imposed on the profits of a similar enterprise of the first-mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7 of this Agreement.

3. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to persons not resident in that State any personal allowances, reliefs, reductions and deductions for taxation purposes which are by law available only to persons who are so resident.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances.

5. The provisions of paragraphs 2 and 4 of this Article shall not apply to the Vietnamese profit remittance tax, which in any case shall not exceed 10 per cent of the gross amount of profits remitted, and the Vietnamese taxation in respect of agricultural production activities.

6. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Agreement.

ARTICLE 26

Mutual Agreement Procedure

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Agreement, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those State, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. This case must be presented within three years of the date of receipt of notice of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representative of the competent authorities of the Contracting State.

ARTICLE 27

Exchange of Information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of the Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement, in so far as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of the State. However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting State, it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall, through consultation,

develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchange of information shall be made, including, where appropriate, exchange of information regarding tax avoidance.

2. The exchange of information or documents shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases or both. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be furnished on a routine basis.

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

ARTICLE 28

Diplomatic Agents and Consular Officers

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

ARTICLE 29

Entry into Force

Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the latter of these notification and shall thereupon have effect :

- (a) in India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the latter of the notifications is given;
- (b) in Vietnam :
 - (i) in respect of taxes withheld at source, in relation to taxable amount paid on or after 1 January following the calendar year in which the Agreement enters into force;

- (ii) in respect of other Vietnamese taxes, in relation to income, profits or gains arising in the calendar year following the calendar year in which the Agreement enters into force, and in subsequent calendar years.

ARTICLE 30

Termination

This Agreement shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, given the other Contracting State through diplomatic channels, written notice of termination and, in such event, this Agreement shall cease to have effect :

- (a) in India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice is given;
- (b) in Vietnam :
 - (i) in respect of taxes withheld at source, in relation to taxable amount paid on or after 1 January following the calendar year in which the notice of termination is given;
 - (ii) in respect of other Vietnamese taxes, in relation to income, profits or gains arising in the calendar year following the calendar year in which the notice of termination is given, and in subsequent calendar years.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE in duplicate at Hanoi this 7th day of September one thousand nine hundred and ninety four in Hindi, Vietnamese and English languages. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of
the Republic of
India.

Sd/-

H.E. Mr. Bhuvnesh Chaturvedi
Minister of State

For the Government of
the Socialist Republic of
Vietnam.

Sd/-

Illegible
Minister of Finance

Prime Minister's Office

[Notification No. 9758/95/F. No. 503/7/91-FTD.]

V. B. SRINIVASAN, Jt. Secy.

